INDEX

Starred Assembly Question No. *9

Starred Assembly Question Diary No. *14/18/170

Listed on 21.02.2024

Sr. No.	**Particulars**	**Page No.**
1.	Reply of Starred Assembly Question No. *9 (in English)	1-3
2.	Reply of Starred Assembly Question No. *9(in Hindi)	4-6

Award of 1128 Acre Land

***14/18/170 SH. SATYA PRAKASH, M.L.A (Pataudi)**:- Will the Deputy Chief Minister be pleased to state that:

a) The time by which interest on an amount of compensation for 1128 acre land acquired in Panchgaon, Manesar from the date of award and upto the date of release of fund is likely to be given;

b) The time by which compensation of 912 acre acquired land of Manesar is likely to be released; and

c) The time by which 27 acre land acquired in Manesar is likely to be released?

Reply:-

Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Haryana.

Sir,

A Statement is laid on the Table of the House.

Statement of Sh. Dushyant Chautala, Hon'ble Deputy Chief Minister
In reply to Award of 1128 Acre land

a) As per the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, payment of interest is to be made from the time of taking possession until payment is made. In the present case, the Award was passed on 21.04.2011 but possession could not be taken due to stay granted by the Hon'ble Supreme Court and therefore, the interest was declined by the DRO-cum-LAC which has been challenged by the landowners by filing writ petitions. The writ petitions were disposed off with directions to avail appropriate civil remedy as question of fact is involved. The landowners have challenged the said decision by filing LPA and cross objections have also been filed by HSIIDC and matter is sub- judice and listed for 09.04.2024.

b) As per Judgment dated 12.03.2018 passed by the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No.8788 of 2015 titled Rameshwar and others V/s State of Haryana and others, it has been held that the sale consideration paid by the builders/private entities to the landholders shall be treated towards compensation under the award and the landholders will not be required to refund any amount to such builders/private entities. The landholders will be at liberty to prefer Reference under Section 18 of the Act. References were filed by the landowners which have been decided by the Reference Court vide Awards dated 19.05.2023 and 20.07.2023 thereby enhancing the compensation. The Awards have been further challenged by the HSIIDC before the Hon'ble Punjab and Haryana High Court by filing RFAs which are likely to be listed soon.

c) As per the judgement dated 21.07.2022 passed by the Hon'ble Supreme Court in Misc application no. 50 of 2019 in Civil Appeal No. 8788 of 2015 & connected matters, operative part of Hon'ble Apex Court order dated 21.07.2022 qua 27 acres in question, is reproduced as under:

"With respect to Dharamveer and other petitioners, as well as similarly placed individuals the rights and title in respect of lands under their occupation is vested with HSIIDC. It is up to the HSIIDC to frame such scheme as is permissible in accordance with its parent enactment and a non-discriminatory manner by a scheme, in regard to such land (i.e., the 27 acres to which the petitioners and others like them may claim relief) as it may deem appropriate. In case the HSIIDC chooses to do so, it shall be bound by all provisions of the Master Plan and Zoning and such other rules and regulations as are applicable, in the area and shall strictly enforce them."

There are no directions for release of 27 acres land by the Hon'ble Apex

Court. Liberty has been granted to the Corporation to frame a policy for which a survey has been conducted by HSIIDC. Duly conducted survey shows that structures exist in scattered form on the said land. Ground truthing is being done to verify the data collected through the survey. Since, it is a policy matter, therefore, after detailed examination and considering planning parameters, a proposal will be submitted by HSIIDC to the State Government for appropriate decision.

1128 एकड़ भूमि का अधिनिर्णय (अवार्ड)

*9 श्री सत्य प्रकाश (पटौदी):

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः-

क) पंचगांव, मानेसर में अधिगृहित 1128 एकड़ भूमि के लिए मुआवजे की राशि पर अधिनिर्णय (अवार्ड) की दिनांक से निधि जारी होने की दिनांक तक, ब्याज कब तक दिए जाने की संभावना है;

ख) मानेसर की अधिगृहित 912 एकड़ भूमि का मुआवजा कब तक जारी किये जाने की संभावना है; तथा

ग) मानेसर में अधिगृहित 27 एकड़ भूमि कब तक मुक्त किये जाने की संभावना है ?

उत्तरः

श्रीमान जी,

कथन सदन के पटल पर रखा गया है।

<u>कथन</u>

<u>1128 एकड़ भूमि का अवार्ड</u>

श्री दुष्यन्त चौटाला, माननीय उप मुख्य मंत्री द्वारा 1128 एकड़ भूमि के अधिनिर्णय (अवार्ड) के संदर्भ में दिया गया कथन।

क) भूमि अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार ब्याज का भुगतान कब्जा लेने के समय से भुगतान करने तक किया जाना है। वर्तमान मामलों में अवार्ड दिनांक 21.04.2011 को परित किया गया था किन्तु कब्जा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे के कारण नहीं लिया जा सका तथा इसलिए ब्याज डी.आरओ एवं एल.ए.सी. द्वारा अस्वीकृत कर दिया था जिसे रिट याचिका दायर करके भूस्वामियों द्वारा चुनौती दी गई है। रिट याचिकाओं को तथ्य का प्रश्न होने के अनुसार उचित सिविल उपाय का लाभ उठाने के निर्देषों सहित निपटान कर दिया या था। भू-स्वामियों ने एल.पी.ए. फाईल करते हुए कथित निर्णय को चुनौती दी गई है तथा एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा क्रास आक्षेप फाईल किए गए हैं तथा मामला दिनांक 09.04.2024 के लिए न्यायाधीन है।

ख) सिविल अपील नम्बर 8788/2015 शीर्षक रामेश्वर एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.03.2018 के निर्णय के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि भू-स्वामियों को निर्माताओं/प्राईवेट हस्तियों द्वारा भुगतान विक्रय प्रतिफल को अवार्ड के अधीन मुआवजे की ओर माना जाएगा तथा भू-स्वामियों के लिए ऐसे निर्माताओं/प्राईवेट हस्तियों को कोई राशि वापिस करना अपेक्षित नहीं होगा। भूस्वामियों को अधिनियम की धारा -18 के अधीन निर्देश को अधिमान देने के की स्वतन्त्रता होगी। भूस्वामियों द्वारा निर्देश फाईल किए गए थे जिसे निर्देश न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2023 तथा 20.07.2023 के अवार्ड द्वारा निर्णीत किए गए हैं जिसके द्वारा मुआवजा बढाया गया है। अवार्ड को एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा आगे आर.एफ.ए. फाईल करके माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती दी गई है जो कि शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने सम्भाव्य है।

ग) सिविल अपील नम्बर 8788/2015 में विविध आवेदन नम्बर 50/2019 तथा अन्य सम्बन्धित मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.07.2022 के निर्णय अनुसार प्रश्नगत 27 एकड़ के सम्बन्ध में माननीय शीर्ष न्यायालय का दिनांक 21.07.2022 के आदेश का प्रवर्तनशील भाग निम्न अनुसार पुनः दोहराया जाता है:-

"With respect to Dharamveer and other petitioners, as well as similarly placed individuals the rights and title in respect of lands under their occupation is vested with HSIIDC. It is up to the HSIIDC to frame such scheme as is permissible in accordance with its parent enactment and a non-discriminatory manner by a scheme, in regard to such land (i.e., the 27 acres to which the petitioners and others like them may claim relief) as it may deem appropriate. In case the HSIIDC chooses to do so, it shall be bound by all provisions of the Master Plan and Zoning and such other rules and regulations as are applicable, in the area and shall strictly enforce them."

यहां माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा *27* एकड़ भूमि को छोड़ने के लिए कोई निर्देश नहीं है। निगम को एक नीति बनाने की स्वतन्त्रता दी की गई है जिसके लिए एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है। विधिवत किया गया सर्वेक्षण दर्शाता है कि कथित भूमि पर बिखरे हुए रूप में संरचनाएं विद्यमान हैं। जमीनी सच्चाई का सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त डाटा का सत्यापन किया जा रहा है। चूंकि यह एक नीति मामला है, इसलिए, विस्तृत जांच तथा योजना पैरामीटरों पर विचार करने के बाद एक प्रस्ताव उचित निर्णय के लिए एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।